भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4025
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

मध्य प्रदेश को पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित धनराशि

4025. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवंटित/स्वीकृत/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) जारी की जाने वाली बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान अभी तक खंडवा जिले सहित मध्य प्रदेश में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) मध्य प्रदेश में योजना की पहुंच के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क), (ख), (ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। मंत्रालय पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई मांग आधारित प्रकृति की है और पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के तहत राज्यवार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है।

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत शुरूआत से मध्य प्रदेश में 58 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी परियोजना लागत ₹1164.45 करोड़ है और ₹386.54 करोड़ की अनुदान सहायता/सब्सिडी स्वीकृत की गई है। अब तक इन 58 परियोजनाओं के लिए ₹244.44 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभ से खंडवा जिले सहित मध्य प्रदेश में स्वीकृत 58 परियोजनाओं में से 29 परियोजनाएं प्रचालनरत हैं, जिनसे 87,191 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, योजना की शुरुआत से ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियों और एक्सपो, क्रेता-विक्रेता बैठकें, मंत्रालय की वेबसाइट आदि के माध्यम से लाभार्थियों के बीच जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने और वृद्धि के लिए विभिन्न पहल की गई हैं।

*****